वित्त विभाग द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

पत्रांक–7/पद सृजन–15–03/2020सा0प्र0 ....5223.../

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक, शालिग्राम पाण्डेय,
सरकार के अवर सचिव (प्र0)।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक...4.5.21...

विषयः– **गया, कटिहार, मधुबनी, नवादा, सुपौल एवं वैशाली न्यायमंडल के अंतर्गत नीमचक बथानी, मनिहारी, फुलपरास, जयनगर, रजौली, त्रिवेणीगंज, निर्मली एवं महुआ अनुमंडल न्यायालय में सबजज एवं मुंसिफ के एक–एक पद अर्थात् कुल 16 (सोलह) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक–44846 दिनांक 23.10.2020 द्वारा गया, कटिहार, मधुबनी, नवादा, सुपौल एवं वैशाली न्यायमंडल के अंतर्गत नीमचक बथानी, मनिहारी, फुलपरास, जयनगर, रजौली, त्रिवेणीगंज, निर्मली एवं महुआ अनुमंडल न्यायालय में सबजज एवं मुंसिफ के एक–एक पद अर्थात् कुल 16 (सोलह) पदों के सृजन पर कुल अनुमानित वार्षिक व्यय ₹ 2,10,36,787/– (दो करोड़ दस लाख छत्तीस हजार सात सौ सतासी रुपये) मात्र की अनुशंसा संसूचित की गयी।

2. उक्त अनुशंसा पर सम्यक् विचारोपरांत महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के उक्त पत्र के साथ संलग्न व्यय विवरणी में अंकित पद संवर्ग के सम्मुख वेतनमान में ₹ 2,10,36,787/– (दो करोड़ दस लाख छत्तीस हजार सात सौ सतासी रुपये) मात्र के वार्षिक व्यय तथा न्यायिक सेवा संवर्गों में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत भत्तों के अनुमानित व्यय भार पर गैर योजना मद में स्थायी रूप से गया, कटिहार, मधुबनी, नवादा, सुपौल एवं वैशाली न्यायमंडल के अंतर्गत नीमचक बथानी, मनिहारी, फुलपरास, जयनगर, रजौली, त्रिवेणीगंज, निर्मली एवं महुआ अनुमंडल न्यायालय में सबजज एवं मुंसिफ के एक–एक पद अर्थात् कुल 16 (सोलह) पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उपर्युक्त सृजित किये जाने वाले पद का व्यय–बजट शीर्ष "2014 न्याय प्रशासन–लघु शीर्ष–105 सिविल और सेशन्स न्यायालय उपशीर्ष–0001 सिविल और सत्र न्यायालय के अन्तर्गत वेतन एवं भत्ते मद से वहन किया जायेगा, जिसका विपत्र कोड सं0–"N–2014001050001" होगा एवं संबंधित जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

4. इसमें प्रशासी पद वर्ग समिति की स्वीकृति एवं मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नकः–व्यय विवरणी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
04.05.2021
(शालिग्राम पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव (प्र0)।

ज्ञापांक–7/पद सृजन–15–03/2020सा0प्र0 ......5223..../पटना–15, दिनांक...4.5.21......

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक–44846 दिनांक 23.10.2020 के प्रसंग में/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 30.04.2021 के मद संख्या–4 के प्रसंग में/संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
04.05.2021

सरकार के अवर सचिव (प्र0)।

संचिका संख्या–7/पद सृजन–15–03/2020

Statement of Annual Estimated Expenditure Chart

Sl. No.	Name of the Post	No. of Post	Pay Scale (P.S.)	Average pay/ Basic pay (Upper Limit of P.S. + Lower Limit of P.S.)/2	Annual Pay (Average Pay x Number of Post x 12)	Dearness Allowance @ 164%	Total Annual Estimated Expenditures
1.	Sub Judge	8	39530-920-40450-1080-49090-1230-54010	46770/-	4489920/-	7363469/-	11853389/-
2.	Munsif	8	27700-770-33090-920-40450-1080-44770	36235/-	3478560/-	5704838/-	9183398
						Total RS.	**21036787/-**

{(Total (in words) : Rupees Two Crore, Ten Lakh, Thirty Six Thousand, Seven Hundred and Eighty Seven Only}

In addition to above mentioned expenditure other allowances as admissible to the officers of Judicial service from time to time shall also be payable.

04.05.2021

(शालिग्राम पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव (प्र0)।